

12 hrs.

## (iii) Need for Providing Training and Other Facilities to Fishermen

श्री बाबूराम परांजपे (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा गैरमछुआ समुदाय के लोगों को ब्लॉक-ग्राम पंचायत स्तर तक मत्स्याखेट का प्रशिक्षण देते हुए उन्हें नाव-जाल आदि उपकरण एवं आर्थिक सहयोग, तथा शासकीय जलाशयों, ग्राम पंचायत के तालाबों में मत्स्याखेट-मत्स्य-पालन हेतु नव-प्रशिक्षित लोगों के जाति समूहों को प्राथमिकता पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

नदी, तालाब, समुद्र भारत की प्राकृतिक सम्पदाएं हैं। इतिहास साक्षी है कि वैदिकयुग के पूर्व से ही निषाद, धीवर, केवट आदि मछुआ-नाविक जाति समूह मत्स्याखेट द्वारा ही अपनी आजीविका निर्वाह करते आ रहे हैं। अपने वंशानुगत स्वतंत्र मत्स्याखेट घन्घे के उपरान्त भी ये अपना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्तर उन्नत नहीं कर सके। आज यह समुदाय सर्वाधिक पिछड़ा, शोषित, पीड़ित, बेरोजगारी एवं भुखमरी से जकड़ा है। पिछड़ा वर्ग आयोग इसे डिप्रेसिड बैकवर्ड क्लास मानता है।

शासन द्वारा क्रियान्वित विश्व बैंक की गैर मछुआ समूह को प्रशिक्षण, साधन, रोजगार की प्राथमिकता प्रदान करने की योजना से ऐतिहासिक वंशानुगत मछुआ जाति समूह अब रोजगार के साधन होते हुए पूर्णतया बेरोजगारी एवं बरबादी की कगार पर खड़ा हो चुका है।

बेरोजगारी उन्मूलन की शासन द्वारा युक्त उक्त योजना ने एक नयी राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न कर दी है।

शासन से पुरजोर मांग है कि देश में करोड़ों की आबादी वाले वंशानुगत मछुआ समुदाय को ही सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार

पर प्रशिक्षण, उपकरण सहायता, जलाशयों में रोजगार की प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण, उपकरण सहायता, जलाशयों में रोजगार की प्राथमिकता, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना एवं बैंकों में विशिष्ट प्रावधान रखते हुए अधिकतम एवं सुलभता से ऋण प्रदान कराते हुए योजनाबद्ध कल्याण किए जाने के निर्देश दिए जावें।

SHRI M.M. LAWRENCE (Iddukki) :

MR. SPEAKER : I have not allowed anything which is against law which is against all decency without foundation I cannot allow anything. Mind you, tomorrow somebody may say something incriminatory against you. This is very irresponsible on your part, I am not going to allow, absolutely not. Mind you, tomorrow somebody may say against you and then you will object to it.....

(Interruptions)\*\*

No, absolutely not. Paper is not a gospel of truth. Until and unless you give some substantive motion against somebody.....

(Interruptions)\*\*

No, not allowed. Don't force my hand. Not a single word is going on record. Illegal. It is very bad on your part, I tell you.....

(Interruptions)\*\*

You go to the court, not here. Until and unless some substantive motion comes. I cannot allow anything to go on record against any honourable person.....

(Interruptions)\*\*

They are mis-utilising, it is very bad on their part. Very irresponsible.

## (iv) Need for Black-Listing a Tea Company Involved in Tax Evasion.

श्री चन्द्रपाल शैलानी : (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के आयकर अधिकारियों ने एक बड़ी चाय कम्पनी के कार्यालय में छापा मार कर चाय की बिक्री व निर्यात से सम्बन्धित बीजक में कम मूल्य दिखा कर किया जाने वाला करोड़ों

का घोटाला पकड़ा है। गत सप्ताह उक्त कम्पनी के चार बड़े अफसरों के निवास स्थानों पर भी छापे मारे गए और कई खाता-बहियाँ जब्त कर ली गई। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन बहियों से मूल्य कम दिखाकर दो करोड़ रुपये की हेराफेरी तथा चार अफसरों के नाम से जमा व निवेश के रूप में लगभग चालीस लाख रुपये के अवैध धन का पता चला है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कम्पनियों तथा बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा इस प्रकार के घोटालों तथा हेरा-फेरी करने के मामले प्रकाश में आये हैं जो सरकारी टैक्सों की चोरी करते हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार ऐसी कम्पनियों को ब्लैक लिस्टेड कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करे।

(v) **Re decision of Bangladesh Government to Sell properties of Indians in Bangladesh**

SHRI CHITTA BASU (Barasat): The Government of Bangladesh have decided to sell by auction or otherwise dispose of their property by the end of this month.

When Indo-Pakistan war broke out in 1965, the Pakistan Government enacted the Defence of P. kistan Ordinance and made rules thereunder for taking over property of Indians in Pakistan as enemy property. The custodians were to manage the property vested in them but the ownership did not vest with them. But with the end of the war, following the Tashkent Accord, Pakistan did not release the vested property to the original owners.

Bangladesh emerged as a separate Independent nation state in 1971. There has never been any war between Bangladesh and India. On the contrary, there exists a Treaty of Friendship between the two countries. So there is no longer any scope for taking over fresh Indian property in Bangladesh and treating the same vested enemy property.

One should also take note of the fact that Pakistan Government took over some Indian property in East Pakistan, but not the properties of which the East Pakistan residents were in possession though some of their co-shares had gone to India and become Indian citizens. The Bangladesh Government has directed its Revenue authorities to search out all such properties and take over them as vested property.

This action means the loss of thousands crores of rupees worth property by Indian owners, and also eviction from their housesteads and agricultural lands of millions of Hindus and other minorities.

I demand that a statement may be made by the Minister of External Affairs in this regard.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur); It is very important, Sir. I hope somebody takes note of it.

(vi) **Need to Check Uncontrolled Mining in Saur Valley in Pithoragarh**

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): मसूरी व दून वैली को लाईमस्टोन्स क्वेरीज से उत्पन्न भू-क्षरण व प्रदूषण के खतरे को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस एवं व्यावहारिक पहल हो भी नहीं पाई थी कि उत्तरप्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ अन्य स्थानों विशेषकर पिथौरागढ़ जनपद में सौर वैली के लिए भी अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है।

सौर वैली को पिथौरागढ़ शीर्ष पर मैग्नेसाइट खानों में हो रहे अव्यवस्थित खनन से खतरा पैदा हुआ है। पिथौरागढ़ में चंडाक बतही नामक स्थानों में दो प्राइवेट कंपनीज को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा खनन की अनुमति दी गई है, परंतु इनके द्वारा खनन कानूनों का सतत उल्लंघन किया जा रहा है। खुले खनन,